भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1119

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2024

7 श्रावण, 1946 (शक)

खेल अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु योजनाएं

1119. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री संजय दीना पाटिल:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खेल अवसंरचना विकसित करने में सक्षम है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश में खेल अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है और

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की शहरों के विद्यमान खेल अवसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की महाराष्ट्र राज्य में कोई खेल अवसंरचना विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास स्कूलों में खेल अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजनाएं हैं और महाराष्ट्र राज्य की विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) खेल राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी, मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है। हालाँकि, खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन" घटक के तहत, यह मंत्रालय खेल परिसर, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी मैदान, सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल मैदान, बहुउद्देशीय हॉल, स्विमिंग पूल आदि जैसे खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत, सरकार महाराष्ट्र सहित पूरे देश में खेल सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न संस्थानों और संबंधितों को सहायता प्रदान करती है।

अब तक, इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की 343 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ङ) वर्ष 2018-19 से जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में कक्षा VI से XII तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम को लागू कर रहा है। इस स्कीम के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्रों को खेलों में प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने ईएमआरएस में 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र (खेलों के लिए सीओई) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा स्कीम के तहत , स्कूलों में खेल, शारीरिक कार्यकलापों, योग, को-करीकुलर कार्यकलापों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा घटक की शुरुआत

की गई है। सरकारी स्कूलों में खेल उपकरणों के लिए प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रति वर्ष 25,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के अंतर्गत 812.42 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, इस स्कीम के तहत गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता के रूप में सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक आधार पर समग्र स्कूल अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस धनराशि का उपयोग खेल के मैदान के रखरखाव तथा उपभोज्य और गैर-उपभोज्य दोनों प्रकार की खेल सामग्री की खरीद के लिए किया जाता है।

(च) सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देशभर के खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त खेल अवसंरचना और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की हैं। यह खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, एनएसडीएफ ओलंपिक पोडियम स्कीम और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से हासिल किया गया है।

****